ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October- 2021
Innovation The Research Concept

कोविड-19 का वैश्विक भू-राजनीति पर प्रभाव

Impact of COVID-19 on Global Geopolitics

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 23/10/2021, Date of Publication: 24/10//2021

इन्द्रेश कुमार
सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान
दिग्विजय नाथ पी0जी0 कॉलेज, गोरखपुर, भारत

कोविड-19 संकट अन्तर्राष्ट्रीय भू-राजनीति को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। शीत युद्ध के बाद कोविड-19 ने भू-राजनीति को पुनः केन्द्र में ला दिया है। इसने अमेरिका-चीन टकराव व चीन की नव साम्राज्यवादी नीति को तीव्रता प्रदान की है। इस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कमजोरी और वैश्विक चिकित्सा प्रबंधन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई है। इससे राष्ट्रवाद के उभार को बल मिला है और वैश्वीकरण के मार्ग में बाधायें खड़ी हुई है। प्रवासी श्रम के व्यापक विस्थापन के कारण सामाजिक समरसता भी प्रभावित हुई है। आज आवश्यकता है कि इस अदृश्य शत्रु से लड़ने में महाशक्तियाँ एकजुटता प्रदर्शित करें तथा आर्थिक लाभ का मोह त्यागकर मानव हित के लिए अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करें।

The COVID-19 crisis has affected international geopolitics at a very deep level. After the Cold War, COVID-19 has brought geopolitics back into focus. This has intensified the US-China conflict and China's neo-imperialist policy.

The deteriorating state of the global economy, the weakness of the World Health Organization, and the true state of global medical management have been exposed by this pandemic. This has given impetus to the rise of nationalism and has created obstacles in the path of globalization.

Social harmony has also been affected due to the widespread displacement of migrant labour. Today, there is a need that the superpowers should show solidarity in fighting this invisible enemy and ensure optimum use of their resources for human interest by sacrificing economic benefits.

मुख्य शब्द भू-राजनीति, वैश्वीकरण, राष्ट्रवाद, बहुध्रुवीयता, पूँजीवाद, कोरोना वायरस।
Geopolitics, Globalization, Nationalism, Multipolarity, Capitalism, CoronaVirus.

प्रस्तावना

कोरोना वायरस की तीव्रता और प्रसार दुनिया के लिए अभूतपूर्व रहा है। इससे पहले भी सभी महामारियों का असर या तो छोटे क्षेत्रों पर हुआ था या कुछ ही समय में ये खत्म हो गयी थी। लेकिन कोविड-19 अल्पकाल में ही पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चिकित्सा और शोध में व्यापक प्रगति के बाद भी शोध संस्थान तथा दवा कम्पनियां अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं खोज पायी हैं। इस महामारी ने वैश्विक भू-राजनीति के सभी पक्षों पर अपना व्यापक प्रभाव डाला है।

उद्देश्य

कोविड-19 के भू-राजनैतिक प्रभावों का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना तथा इसके नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करने का उपाय सुझाते हुए वैश्विक सहयोग को मानव हित के लिए प्रभावी बनाना।

विषय विस्तार

चीन के वुहान शहर में यह स्थानीय बीमारी के रूप में शुरू हुआ और कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया में फैल गया।[1] लाखों लोग जान गंवा चुके है। रोजाना हजारों लोगों को शिकार बनाने के अलावा कोरोना वायरस संकट का सबसे स्पष्ट प्रभाव समूची दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और समाजिक उथल-पुथल के रूप में नजर आया, वायरस अल्प समय में भी पूरी दुनिया में फैल गया। यात्री विमान सेवाएं बन्द कर दी गयी। दुनिया भर में पर्यटन थम गया और मनोरंजन जैसे प्रमुख उद्योग भी कुछ हफ्तों में बन्द हो गये। देश अपने आप में सिमट गये। उन्होंने सीमाएं बन्द कर ली और जनता के आवागम पर ढेरों प्रतिबन्ध लगा दी। करोना वायरस ने वैश्वीकरण को करारा झटका दिया है।[2]

वायरस संकट का वैश्विक प्रभाव बहुत ज्यादा है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताविक वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले ही मंदी आ चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है 1.25 अरब कामगार यानि वैश्विक श्रम बल का लगभग 38 प्रतिशत हिस्से के रोजगार पर संकट आ गया है।3 क्योंकि वे सभी परिवहन, मनोरंजन, खेल, विनिर्माण, खुदरा

निर्माण जैसे उद्योगों में कार्यरत है, जो पूरी तरह से ठप हो गया है। दुनिया भर के शेयर बाजार बैठ गये हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाने वाले तेल उद्योग के सामने पिछले 100 वर्षो का सबसे गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने से और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में बाधा पड़ने से रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। 2008-09 के वित्तीय संकट, 11 सितम्बर के आतंकी हमलें, 1997 के एशियाई वित्तीय संकट, 1991 के सोवित संघ के विघटन जैसे पिछले संकटों के मुकाबले कोरोना वायरस का संकट अधिक बड़ा और गहरा है। इसके सही असर का अंदाजा जो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अत्यन्त भयावह है।[4]

शीत युद्ध समाप्त होने के बाद से ही बहुध्रुवीय विश्व तैयार होने लगा था। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका और चीन की प्रतिस्पद्र्धा तीव्र तकनीक एंव व्यापार युद्ध की शक्ल में सामने आया है और तेज होता जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में आपसी तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका ने पहले ही कोविड-19 को "चाइना वायरस" कह कर इस संकट की तोहमत चीन पर जड़ दी है।5 चीन ने इन आरोपों का पुरजोर विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद में वायरस पर चर्चा कराने के अमेरिकी प्रयास को चीन ने विफल कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार से अमेरिकी नीतियों में परिवर्तन सम्भावित है। पहले बेल्ट एण्ड रोड़ इनीशिएटिव और और अब कोरोना वायरस संकट के बल पर चीन दुनिया में अपना प्रभाव और बढ़ाने की उम्मीद कर सकता है।

कोरोना संकट के साए में अमेरिका और चीन जैसे दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच टकराव से वैश्विक राजनीति पर गम्भीर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्ति की जा रही है। इसका प्रहला प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में सम्पन्न व्यापार समझौते पर होगा। साथ ही, इस घटना क्रम में चीन की लापरवाही भरे कदम के कारण उसे संदेह की नजर से देखा जा रहा है।6 कोरोना वायरस की आपदा ने एक दूसरे धुर विरोधी रहे ईरान और अमेरिका को नजदीक ला दिया है, जिससे तृतीय विश्वयुद्ध का सम्भावित खतरा टलता नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के केन्द्र के रूप में चीन विख्यात होने से दुनिया भर में चीन के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव में इजाफा होने की आशंका है।[7] चीन को विनिर्माण क्षेत्र में अपना प्रभाव पुनस्र्थापित करने में कई दशक तक संघर्ष करना पड़ सकता है। जिससे उसकी नव-सम्राज्यवादी नीतियों पर विराम लग सकता है।

अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिग को रोक दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन "अपने मूल कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है और इसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए" और "झूठी खबर" फैलाने के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराया, जिससे सम्भवतः वायरस का व्यापक प्रकोप हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वाथ्य संगठन के बजट में सर्वाधिक योगदान देता है। 2019 में $ 400 मिलियन से अधिक का योगदान दिया है, जो इसके बजट का लगभग 15 प्रतिशत है।[8] इस कार्यवाही के बाद हाउस ओवरसाइट समिति के रिपब्लिकन सदस्यों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक को लिखे गये पत्र में अनुरोध किया गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना वायरस महामारी के लिए व्यापक रूप से आलोचना कि गई प्रतिक्रिया के बारे में चीन के साथ अपने सम्बन्धों के बारें में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ताइवान से सम्बन्धित एक और विवाद के केन्द्र मे भी रहा है। ताइवान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया है कि उसने चीन को खुश करने के लिए कोरोना वायरस के प्रसार को गम्भीरता से नहीं लिया। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताइवान को पर्यवेक्षक के दर्जे से हटा दिया था जिसकी अमेरिका बहाली चाहता है। इस महामारी के मध्य में ताइवान दुनिया के दूसरें सबसे बड़े मास्क आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और महामारी को भी पूर्ण रूप से नियन्त्रण में किया है। अमेरिका ताइवान का खुला समर्थन करते हुए बीजिंग के खिलाफ ज्।प्म्प् अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है।[9]

कोरोना वायरस के काल में एशियाई समुद्री क्षेत्र में चीन ने आक्रमक भ-ूराजनीति को धीमा नहीं किया है। इसके अलावा इसने सभी आरोपों का मुकाबला करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में दो अनुसंधान केन्द्र को स्थापित किया है और एक वियतनामी मछली पकड़ने वाली नाव को डुबो दिया है इसके अलावा चीन ने 16 मार्च को ताइवान के तट पर एक अभूतपूर्व नाइट एयर ड्रिल आयोजित की और एक छः-जहाजों का बेड़ा भेजा, जो ताइवान के सबसे उत्तरी सिरे के पूर्व मियाको स्ट्रेट के माध्यम से रवाना हुआ था।[10] ताइवान के समर्थन में अमेरिका 25 मार्च से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य विमानों द्वारा कड़ी निगरानी रख रहा है। यह दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, जो एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से गुजर रही है।

कोरोना संकट ने एक बार फिर बहुपक्षवाद की कमजोरियाँ उजागर कर दी है जबसे संकट गहराया है, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर हो रहा है। ज्यादात्तर देश अपने ही भरोसे है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तो संकट पर चर्चा भी नहीं कर सका विश्व स्वास्थ्य संगठन विवादों से घिरा है। जी-20 देशों ने एक जुट होकर भी कुछ नहीं किया। विश्व व्यापार संगठन पिछले कई वर्षो से गहरें संकट में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने के आई0एम0एफ0 के अनुमान से बुरी तरह से घबराहट फैल गयी है। लाखों नौकरियां जाने तथा आई0एल0ओ0 के अनुमानों से घबराट और भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि बहुपक्षवाद को खतरा विल्कुल भी नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की बाते हर कोई करता है, लेकिन अधिकत्तर बड़े देश 'पहले में' की नीति पर चलते हैं। कोरोना के बाद दुनिया में राष्ट्रवाद या अतिराष्ट्रवाद बढ़ने की आशंका की जा सकती है। क्षेत्रीय संगठन भी सक्रिय नहीं दिखे, इटली के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है की संकट के समय यूरोपीय संघ की निष्क्रियता से यूरोपीय परियोजना खत्म हो सकती है। यूरोपीय संघ का 500 अरब यूरो का पैकेज बहुत देर में आया है और बहुत कम भी है।[11]

दुनिया को नौकरियाँ बचाने, अर्थव्यवस्था के संकट में पड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने और सबसे गरीब तथा वंचित तबको की आजीविका की समस्या हल करने के लिए वैश्विक योजना की जरूरत है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। कई देशों ने आपात ऋण के लिए आई0एम0एफ0 से गुहार लगायी है। यह संकट कई देशांे की अर्थव्यस्था को मृतप्राय कर दिया है, इससे व्यापक अशांति और अस्थिरता फैली है।

अंधाधंुध उपभोक्तावाद पर आधारित पूंजीवादी मॉडल पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अनियन्त्रित वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के बीच बहुत अधिक असमानता फैल गई है। वैश्विकरण का जोर सम्पदा के सृजन पर है उसके वितरण पर नहीं । अंधाधंुध उपभोक्तावाद टिकने वाला नहीं है। क्योंकि इसके कारण जलवायु परिवर्तन तेज हो गया और पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। बार-बार प्राकृतिक आपदायें आने से एक के एक देश बर्बाद होते रहे, लेकिन टिकाऊ विकास के व्यवहारिक उपायों पर कम विचार किया गया है। जैव विविधता को सोचे समझे वगैर नष्ट करने से मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। मनुष्य और जन्तु के बीच घनिष्टता के कारण जन्मे कोरोना वायरस ने विकास के उपभोक्तावादी मॉडल की कमजोरी उजागर कर दी है। कोविड-19 के बाद दुनिया में राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा है, देश एक बार फिर सीमाओं पर नियन्त्रण बढ़ा रहे हैं, जिसका मुक्त हवाई यात्रा और मुक्त व्यापार पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका ने अफगान युद्ध, ईराक युद्ध, 11 सितम्बर के आंतकी हमले और खाड़ी में हुए नुकसान से अधिक नुकसान कोरोना वायरस के कारण उठाया है और सुरक्षा पर हर वर्ष सैकड़ों अरब डालर खर्च करता है मगर उसका स्वास्थ्य तंत्र कमजोर है।12 कोरोना वायरस ने दिखाया है कि पारम्परिक सैन्य सुरक्षा से ज्यादा महत्व स्वास्थ्य सुरक्षा का है। इससे देश सुरक्षा का व्यापक विचार मानने के लिए बाध्य होगें। जिसमें अपारम्परिक सुरक्षा मामलों को अधिक अहमियत दी जायेगी क्योंकि वे ज्यादा नुकसान कर सकते है। कोरोना वायरस के कारण जैव आतंकवाद पर फिर चर्चा होने लगी है।

बेहद करीब से जुड़ी दुनिया में विनिर्माण लम्बी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है। उनमें से अधिकांश श्रृंखलाएं चीन से होकर आती हैं। चीन से गुजरने वाली लम्बी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निश्चित रूप से विचार होगा। छोटी आपूर्ति श्रंृखलाओं पर भी ध्यान देना होगा। देश कई क्षेत्रांे में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण तथा छोटे व मझोले उद्योग आदि पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। कार्यस्थलों मंे तब्दीली होगी, जहाँ दूर से काम करने को बढ़ावा दिया जायेगा। नये तौर तरीके शुरू होगें। आपूर्ति की नयी प्रणाली विकसित की जायेगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणालियों में क्रांन्ति होगी। यात्रा व परिवहन में आमूल-चूल परिवर्तन आयेगा। दैहिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग सुनने में अच्छा लगता है मगर मनुष्य पर इसका मनौवैज्ञानिक असर पड़ेगा, क्योंकि वह मूलतः सामाजिक प्राणी है व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आसानी से नहीं होगा और इसके दुष्परिणाम भी होगें।

इस महामारी में घरेलू तौर पर, भारत ने देश व्यापी तालाबन्दी लागू करने के लिए तेजी से काम किया। क्षेत्रीय स्तर पर, यह विशेष रूप से कोविड-19 प्रकोप के लिए एक सामान्य फण्ड पूल बनाने के लिए सार्क के ढँाचें को पुनर्जीवित करने के लिए सामने से आगे आया। इसके अलावा उसने मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बंाग्लादेश, भूटान, कुवैत, चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय देशों में चिकित्सा दल, सहायता और आपूर्ति उपलब्ध कराई है। भारत, चीन और अमेरिका दोनों को सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। चीन को मास्क, दस्तानें और अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपकरण सहित 15

टन चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। साथ ही अमेरिका को भी हाईड्राक्सीक्लोरोक्वीन निर्यात किया है।[13] महामारी के दौरान ही अफगानिस्तान को गेंहूँ उपलब्ध कराने के फैसले की अमेरिका ने सराहना की है। भारतीय विदेशमंत्री एस0 जयशंकर द्वारा जैविक और विषाक्त हथियारों के सम्मेलन की 45वीं वर्षगाठं मे कोविड-19 का उल्लेख करने से बचने का प्रयास नहीं किया गया। इस बयान ने सम्मेलन के संस्थागत मजबूती के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी शामिल किया गया। जैविक और विषाक्त हथियारों के सम्मेलन के सदस्यों को कहा गया कि कन्वेंशन के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वयं को समर्पित करें।[14] भारतीय और अमेरिकी विदेशमंत्री कोविड-19 महामारी के विरूद्ध भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रणनीति की कार्ययोजना बनाई है। इस रणनीतिक चर्चा में आस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, वियतनाम, न्यूजीलैण्ड और जापान के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी प्रतिनिधियों ने साप्ताहिक आधार पर चर्चा रखने का संकल्प लिया इस साप्ताहिक बैठक की रूप रेखा को ''क्वाड प्लस'' कहा जा रहा है जो आसियान $6 मॉडल को भी अतिव्यापन करता है।[15] भारत-प्रशांत देशों के बीच घटनाक्रम और चर्चा पर चीन पैनी निगाह से देख रहा है। क्वाड प्लस ढांचा मौजूदा स्थिति में भारत के लिए बेहत्तर हो सकता है। महामारी के बावजूद दक्षिण चीन सागर में चीन की निरन्तर आक्रामकता बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने हिन्द महासागर में पानी के नीचे एक ड्रोन बेड़े की तैनाती की, जिसने 3400 से अधिक सूचनाएं एकत्रित की।16 इस घटना ने भारत की इण्डो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में सर्तकता बढ़ाई है।

चीन के डिजिटल घुसपैठ को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत ने 2 सितम्बर तक 224 ऐप पर पाबंदी लगायी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत लद्दाख में जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। पहले से ही डोकलाम विवाद और अरूणाचल प्रदेश में सीमा विवाद जारी है। सरहद एवं तकनीकी दोनों घुसपैठ चीन की दुश्मनी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। चीन के दोनों तरीकों से भारत की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर भारत के साथ जबरजस्त तनाव के बीच नेपाल-चीन संम्बन्धों में आयी निकटता भारत-नेपाल संम्बन्ध को प्रभावित किया है। क्योंकि नेपाल इन दोनों देशांे के बीच 'बफर स्टेट' का कार्य करता है। इन सम्बन्धों को लेकर भारत को सतर्क और सकारात्मक रणनीति अपनानी होगी।

कोविड-19 संक्रमण के दौर में भारत दुनिया के दूसरें देशों को एंटी मलेरिया ड्रग्स एवं वैक्सीन उपलब्ध कराकर मेडिकल डिप्लोमेसी मजबूत कर रहा है। अॉपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को, मिशन सागर के तहत मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को कोविड-19 से सम्बन्धित दवाएं एवं खाद्य आपूर्ति की है।[17] दूर देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए वन्देमातरम् मिशन और आपरेशन समुद्रसेतु चलाया।18 इस महामारी को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हुए भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के समूह सार्क के सदस्य देशों के बीच तारों को एक बार फिर से जोड़ दिया है। सभी देश प्रधानमंत्री मोदी के विडियों कान्फ्रेन्स हाल में न केवल हिस्सा लिये बल्कि इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में संयुक्त तौर पर फण्ड तैयार करने के लिए सहमत भी हुए।[19]

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को नजरअंदाज किये वगैर आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी पर आधारित अर्थव्यवस्था तैयार करनी चाहिए, विनिर्माण क्षेत्र को नये सिरे से तैयार करना होगा। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। यही समय है जब भारत को दूसरे देशो के साथ सार्थक सम्वाद और सहयोग तेज करना चाहिए। और नयी विश्व व्यवस्था को गढ़ने में मदद करनी चाहिए। भू-राजनीतिक विचार और शक्ति राजनीति अहम् बनी रहेगी मगर भारत को वैसुधैव कुटुंबकम, करूणा, टकराव खत्म करने, प्रकृति का सम्मान करने एवं पर्यावरण का ध्यान रखने जैसे विषयों पर आधारित नयी विश्व व्यवस्था तैयार करने में मदद करनी चाहिए। भारत के पास देश के भीतर और पड़ोस आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करने का अवसर है विकास का भारतीय मॉडल भारत की वास्तविकताओं एवं सतत् विकास के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए, जो हमारे सांस्कृतिक विचारों में शामिल है।

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण का व्यापक अभियान चल रहा है भारत में भी कोवैक्सीन, कोविशिल्ड, स्पूतनिक-5 जैसे वक्सीन से रोकथाम व बचाव को गति दे रहा है। भारत ने अपने पड़ोसी एवं विश्व के अन्य देशों में वैक्सीन उपलब्ध कराकर अपने विदेश सम्बन्धों को मजबूत कर रहा है।20 कोविड-19 के खिलाफ यह लड़ाई अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्चता की लड़ाई बन गयी है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और शक्तियों का पुनर्निर्धारण भी हो सकता है। निःसंदेह इस संकट से सही तरीके से निपटने वाली महाशक्ति बदलती वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष

कोविड-19 संकट अन्तर्राष्ट्रीय भूराजनीति को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है जिसमें अमेरिका-चीन टकराव, ईरान और अमेरिका नजदीकी, यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर ब्रिटेन की स्थिति, चीन की नव-साम्राज्यवादी नीति, वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र, तेल की राजनीति, इटली का पर्यटन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, नेपाल-चीन नजदीकी का भारत पर प्रभाव, भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी, वैश्विक चिकित्सा प्रबन्धन, रूस-चीन की नजदीकी, अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति, चीन का बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कमजोरी, प्रवासी श्रम के व्यापक विस्थापन के कारण सामाजिक समरसता की स्थिति, इस्लामिक स्टेट का पुनरूद्धार, ईरान की ध्वस्त अर्थव्यवस्था, अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की कम होती प्रतिबद्धता, हिन्द-प्रशान्त महासागर की सामरिक स्थिति और भारत-चीन सीमा विवाद आदि घटनाओं को इस महामारी ने तीव्रता प्रदान की है। वर्तमान में पूरा विश्व एक गम्भीर संकट के दौर से गुजर रहा है यह समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं बल्कि एकजुटता प्रदर्शित करते हुए इस अदृश्य शत्रु से लड़ने का है। वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए इस महामारी की रोकथाम तथा पूर्णतः उन्मूलन का अनवरत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *www.vifindia. org.* पर अरविंद गुप्ता के लेख से उद्धृत
2. वही
3. वही
4. वही
5. वही
6. *www.drishtiias.com* से उद्धृत
7. वही
8. *www.icwa.in.* पर डॉ0 विवेक मिश्र के लेख से उद्धृत
9. वही
10. वही
11. *www.vifindia. org. ij vjfoan xqIrk ds ys[k ls mn~/k`r*
12. वही
13. *www.icwa.in.* पर डॉ0 विवेक मिश्र के लेख से उद्धृत
14. वही
15. वही
16. वही
17. *www.mea.gov.in.* से उद्धृत
18. वही
19. *www.bbc.com.* पर सचिन गोगोई के लेख से उद्धृत
20. *www.bhaskar.com.* से उद्धृत